03062015-ls-ngp-04.qxd 06/03/2015 2:27 PM Page 1

और ... एक शेर
भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए
मां ने फिर पानी पकाया देर तक
-नवाज़ देवबंदी

लोकमत समाचार
नागपुर, बुधवार, 3 जून 2015

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

छोटी-छोटी खुशियों को पूरे मन से मनाएं. इससे जीवन में उत्साह बना रहता है. ■ अज्ञात

संपादकीय

अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है...!

पिछले दो-तीन दिनों में बच्चों के प्रति माता-पिता के व्यवहार, लगाव तथा जिम्मेदारी को दर्शाने वाली दो परस्पर विरोधी खबरें आईं. पहली खबर यह है कि कोमा में मरणासन्न अपने बच्चे की जिंदगी के लिए एक मां आखिर तक हिम्मत नहीं हारती और चिकित्सा विज्ञान के लाचार हो जाने पर अपनी लोरियों की ताकत के बल पर पुत्र को कोमा से बाहर निकाल ले आती है. एक दूसरे माता-पिता हैं जो स्वस्थ बच्चे को मरणासन्न बनाने पर उतारू हैं. पिता लगातार धूम्रपान करता है और उसकी पत्नी चुपचाप तमाशा देखती रहती है. सिगरेट के धुएं से उनका बच्चा मरणासन्न स्थिति की ओर बढ़ रहा है और एक स्वास्थ्य कर्मचारी रक्षक बनकर अनायास उसके घर पहुंच जाती है. दूसरी घटना इंग्लैंड के एक छोटे से शहर हेल की है जहां स्थानीय अदालत ने बच्चे को बचाने के लिए न केवल कठोर फैसला सुनाया बल्कि दुनियाभर में धूम्रपान करने वाले लोगों को खुद के स्वास्थ्य के अलावा बच्चों की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी के प्रति सचेत भी किया है. हेल शहर की एक स्वास्थ्य कर्मी सर्वेक्षण के दौरान एक घर में गई तो उसे धुएं से भरा हुआ पाया. एक व्यक्ति लगातार धूम्रपान कर रहा था और उसका दो साल का बच्चा बीमार हालत में एक कोने में लेटा हुआ था. डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि सिगरेट के धुएं ने बच्चे की हालत खराब कर दी है. मामला पुलिस से अदालत तक पहुंचा और जज ने फैसला सुनाया कि बच्चे को उसके माता-पिता से अलग कर बच्चों के लिए बने आश्रय स्थल में रखा जाए. धूम्रपान एक विश्वव्यापी समस्या है. दुनिया में सिर्फ धूम्रपान से 60 लाख लोगों की मौत हो जाती है जिनमें एक तिहाई महिलाएं होती हैं. भारत में बीड़ी और सिगरेट के शौकीन 13 लाख लोग बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं. इनमें चार लाख महिलाएं हैं. धूम्रपान से उठनेवाला धुआं हमारे देश में हर साल तीस लाख बच्चों को सांस की बीमारियां दे जाता है. धूम्रपान करने वाली और धूम्रपान से परहेज करनेवाली लेकिन उसके धुएं के आसपास रहनेवाली महिलाओं के गर्भ से हर वर्ष भारत में 25 लाख से ज्यादा बच्चे बीमार हालत में दुनिया में कदम रखते हैं. भारत सरकार ने पांच साल पहले धूम्रपान तथा तंबाकू व उसके उत्पादों के सेवन पर एक सर्वेक्षण करवाया था, उसमें चौंकानेवाले तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में लोग औसतन 17 वर्ष की उम्र से धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं. धूम्रपान तथा तंबाकू सेवन करनेवाली महिलाओं में से 25.8 प्रतिशत तो 15 साल की उम्र से पहले ही व्यसनी हो जाती हैं. धूम्रपान से फेफड़े खराब हो जाते है, कैंसर होता है और हृदय बीमार हो जाता है. भारत में धूम्रपान व तंबाकू सेवन के बढ़ते खतरे के बावजूद दिखावे के लिए कुछ नियम-कायदे बनाए गए हैं. देश में तंबाकू लॉबी इतनी ताकतवर है कि कोई भी सरकार तंबाकू व तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं दिखाती. जब यह निर्विवाद रूप से साबित हो चुका है कि धूम्रपान करना या तंबाकूजन्य पदार्थों का सेवन करना प्राणघातक है तो इस जहर को बनाने व बेचने की अनुमति क्यों दी जा रही है. इंग्लैंड की अदालत का कठोर फैसला यह संदेश भी देता है कि अपने बच्चों से यदि माता-पिता को सचमुच में प्यार है तो उन्हें धूम्रपान जैसे जानलेवा व्यसन छोड़ देने चाहिए. ऐसे अदालती फैसले कुछ लोगों को अस्वीकार्य भी हो सकते हैं लेकिन जब व्यसन बच्चों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो कहीं न कहीं से कठोर पहल की शुरुआत होनी ही जानी चाहिए. ■■

जमीन पर

देश चिकित्सा विज्ञान की असीम बुलंदियों को छूने वाली मंजिल तक पहुंच गया. फिर उसने नीचे झांककर देखा.

लघुकथा

अद्भुत नजारा था. मंजिल के इर्द-गिर्द जमीन पर बिखरे लोग कीड़े-मकोड़ों से भी छोटे नजर आ रहे थे. लेकिन ये लोग थे कौन?

उसने नीचे उतरकर देखा. वही लोग, जो अमूमन हर बड़े अस्पताल के परिसर में इधर-उधर पड़े रहते हैं. कुछ बेड खाली होने का इंतजार कर रहे थे. कुछ रजिस्ट्रेशन फीस तक चुकाने की हालत में नहीं थे, लिहाजा उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा था. कुछ पैसा खत्म हो जाने की वजह से डिस्चार्ज कर दिए गए थे. ■■

पी.के. राय

क्रांतिकारी बदलाव की 'स्मृति'

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

अच्छा हुआ- स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह की धूमधाम के बाद अपनी सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर 'सौ में से सौ' नंबर दे दिए. देश का सर्वोच्च नेता ही परीक्षक हो तो भोली-भाली, गरीब अशिक्षित आधी आबादी कैसे सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा कर सकती है? लाखों लोग तो सौ की गिनती भी ठीक से नहीं जान पाते. हां, सात-करोड़ नए खाते खोलकर खून-पसीने की कमाई से 17 हजार करोड़ अपनी सरकार के खजाने में जमा कर दिए.

इसलिए मोदी सरकार की पहली वर्षगांठ को अपनी 'स्मृति' के साथ नमन करने के बाद अगले चार वर्षों की सुध लें. पहले वर्ष में स्मृति (ईरानी) की दिव्य दिशा से सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई. पर्दे पर भारतीय संस्कृति की 'आदर्श बहू-बेटी' तुलसी का रोल निभाने के बाद इन दिनों वे पर्दे पर रौद्र रूप दिखाने वाली अभिनेत्री की तरह मीडिया को त्रिशूल से धकेलते हुए आगे बढ़ रही हैं. उनकी शिक्षा- दीक्षा या राजनीतिक पृष्ठभूमि और गतिविधियों पर जब संघ तक उंगली नहीं उठा सकता तो भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के कोई बुजुर्ग सदस्य या सांसद अथवा प्रतिपक्ष अथवा चेलापति राव और भानुप्रताप शुक्ल की भिन्न परंपरा वाले निष्पक्ष मीडिया को स्मृति के रथ की दिशा पर कोई प्रश्न उठाने की हिम्मत क्यों होनी चाहिए? वर्षों तक अभिनय की दुनिया में रहने के कारण वह मीडिया के मंच पर किसी को भी पराजित करने में समर्थ मानती हैं. इसीलिए पूरे एक साल में दसियों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त नहीं कर पाने, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को

> स्मृति ईरानी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कई अधिकारी मंत्री की कोप दृष्टि से बचने के लिए अन्य मंत्रालयों में तबादले की गुहार लगाते रहे हैं. कुछ को मंत्री ने हटवा दिया, कुछ खुद चले गए.

अंतर्राष्ट्रीय पैमाने वाली चार वर्षीय डिग्री व्यवस्था को तत्काल बदलने के लिए बाध्य करने, रातोंरात सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन के बजाय संस्कृत लागू करवाने, क्रिसमस को अनुशासन दिवस, शिक्षक दिवस को अपनी सरकार के मानदंड से बाल दिवस के रूप में बदलने, पाठ्य पुस्तकों में व्यापक परिवर्तन करने, आईआईटी के निदेशकों की नियुक्तियों और विचार गोष्ठियों पर अंकुश लगाने का इंतजाम करना उनके 'अपनों' की नजरों में सफलता ही कहा जाएगा. भले ही देश के लाखों स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) के बजट में इस साल भारी कटौती हो गई, केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली के स्कूलों-कॉलेजों और देश के विश्वविद्यालयों की हालत एक साल में और बदहाल हो गई, भाजपा शासित राज्यों में भी पचासों स्कूलों के लिए दस गज की छत और दीवार का अभाव है, कॉलेजों विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की हालत खस्ता हो गई. लेकिन मोदी-स्मृति की सरकार असल में नई पीढ़ी को 'डिजिटल इंडिया' का हिस्सा बनाना चाहती है. कम्प्यूटर, आईपैड, मोबाइल की व्यवस्था पर जोर देने से किताबों-टाटपट्टियों अथवा मेजों की आवश्यकता न्यूनतम हो जाने की आशा सरकार रखना चाहती है. जिन बच्चे-बच्चियों को पीने के शुद्ध पानी के लिए टंकी और प्याऊ तक की व्यवस्था नहीं और जिन गांवों में रात के साथ दिन में भी बिजली नहीं होती, वहां कम्प्यूटर-मोबाइल से 'मेक इन इंडिया' का ज्ञान कैसे मिल सकेगा?

जहां तक नौकरशाही का सवाल है, स्मृति ईरानी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कई अधिकारी मंत्री की कोप दृष्टि से बचने के लिए अन्य मंत्रालयों में तबादले की गुहार लगाते रहे हैं. कुछ को मंत्री ने हटवा दिया, कुछ खुद चले गए और जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई, वे चुपचाप मंत्रीजी के हर आदेश को कागज पर उतार कर जारी कर रहे हैं. जिस मंत्रालय में संपूर्णानंद, भक्तवत्सलम, नूरुल हसन, कृष्णचंद्र पंत, नरसिंह राव, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता तक क्रांतिकारी बदलाव नहीं कर पाए, वहां स्मृति ईरानी ने नया इतिहास बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है. इसीलिए पिछले महीनों के दौरान राजनीतिक गलियारों में भाजपा के ही संतुष्ट अथवा असंतुष्ट नेताओं द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय में बदलाव की अटकलों (क्रांतियों) को विराम मिलने की आशा की जा सकती है. मोदी सरकार का मूल मंत्र उनके अपने मानदंडों के अनुसार सफलता तथा कठोरता है. भारी बहुमत से भाजपा की विजय के कारण बहुत से योग्य, अधिक शिक्षित और अनुभवी सांसद भी संसद में होंगे, लेकिन योग्यता तो सेनापति ही तय कर सकता है. आखिरकार भाजपा के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद भी तो मोदी सरकार के साथ संपूर्ण समन्वय और समर्पण के आधार पर तय हुआ है. संघ और भाजपा को अब 'विश्व विजयी झंडा' और कोहिनूर जड़ित सिंहासन की शान से मतलब है. समस्याएं तो क्या 'राम राज्य' में नहीं रही होंगी और महाभारत के सारथी श्रीकृष्ण को भी कुरुक्षेत्र से दूर गुजरात की द्वारका के जरिए शासन चलाने में सुविधा हुई थी. इसलिए गौरव की स्मृति के साथ देश को आगे-पीछे बढ़ने-हटने के लिए चार साल तक तो धैर्य रखना होगा. ■■

राहुल का आत्मविश्वास कुछ तो असर करेगा

मुकेश कुमार
जाने-माने पत्रकार

जब घनघोर विरोधी भी किसी की तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं तो मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने सचमुच में कुछ ऐसा किया है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. शिवसेना ने राहुल गांधी की निंदा करने या उनकी खिल्ली उड़ाने में कभी भी कंजूसी नहीं दिखाई थी, मगर अब वह भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही है कि निस्तेज हो चुकी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की सक्रियता ने चैतन्य कर दिया है और वह फिर से गतिशील होती नजर आ रही है. हालांकि ये प्रशंसा बिना लाग-लपेट के नहीं थी और उसका इरादा भी राहुल पर हमला करना ही था. खासतौर पर वह उनके सूट-बूट की सरकार वाले सुपरहिट जुमले का जवाब देना चाहती थी.

वैसे शिवसेना की ओर से की गई प्रशंसात्मक टिप्पणी निंदकों की ओर से की जाने वाली पहली तारीफ नहीं थी. इसके पहले गांधी परिवार के खिलाफ अनवरत जहर उगलते रहने वाले रामदेव भी राहुल गांधी के बारे में सकारात्मक टिप्पणी कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस फिर से उठती हुई दिख रही है. ये ऐसा समय है जब मोदी की आलोचना के स्वर तेज होते जा रहे हैं और उन्हें अपने शुभचिंतकों की ओर से समर्थन की दरकार है. ऐसे में यदि वे उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी की पीठ ठोंकने लगें तो इसके स्पष्ट मायने यही निकलते हैं कि राहुल गांधी के सितारे गर्दिश से निकल रहे हैं.

वैसे ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि एकांतवास के बाद लौटे राहुल गांधी ने कांग्रेसजनों में आशा का संचार करना शुरू कर दिया है. रक्षात्मक मुद्रा त्यागकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार को आड़े हाथों लेने लगे हैं. यही नहीं, पार्टी के अंदर राहुल गांधी का विरोध अगर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है तो ये भी सच है कि अब उनकी स्वीकार्यता एकदम से बढ़ गई है. अब सार्वजनिक रूप से उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा है और प्रियंका लाओ देश बचाओ के नारे लगने बंद हो चुके हैं. यानी कांग्रेसजन भी उन्हें ही अपने भाग्य विधाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होते प्रतीत होने लगे हैं.

स्पष्ट है कि आम चुनाव के बाद पस्त पड़ चुकी कांग्रेस अब धूल झाड़कर खड़े होने की कोशिश में लग गई है और इसमें मुख्य योगदान राहुल गांधी का ही है. संसद से सड़क तक उनकी सक्रियता लोगों को भा रही है. इससे भी ज्यादा आकर्षण उनके नए आक्रामक तेवरों का है जो सूट-बूट की सरकार वाले जुमले से शुरू हुआ था. इसके बाद से वे लगातार नरेंद्र मोदी को अपना निशाना बना रहे हैं और दिलचस्प बात ये है कि भाजपा को ठीक से जवाब देते भी नहीं बन रहा है. मोदी की नेतृत्व शैली और संघ परिवार के विवादास्पद बयान उन्हें हमले करने के लिए पर्याप्त मौके दे रहे हैं. वास्तव में कांग्रेसी ऐसे ही नेतृत्व का इंतजार कर रहे थे. मोदी की आक्रामकता ने उनके नट-

> आम चुनाव के बाद पस्त पड़ चुकी कांग्रेस अब धूल झाड़कर खड़े होने की कोशिश में लग गई है और इसमें मुख्य योगदान राहुल गांधी का ही है.

बोल्ट ढीले कर रखे थे और हर मुद्दे पर वे बचाव की मुद्रा में दिखने लगते थे. लेकिन राहुल गांधी के उलट वारों ने स्थिति को अगर उलटा नहीं है तो समान धरातल पर लाकर जरूर खड़ा कर दिया है. यहां से पार्टी खुद के फिर से तनकर खड़े होने का अभियान शुरू कर सकती है.

इसमें कोई दो मत नहीं कि राहुल गांधी को विपक्ष में होने के फायदे मिल रहे हैं. सरकार चलाने के बजाय उसके कामकाज में गलतियां निकालकर इनकी आसान हो जाता है. पहले मोदी और उनकी पार्टी ने इसका लाभ उठाया था. अब राहुल उन्हीं की तरह उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं.ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मोदी से बढ़ते मोहभंग का फायदा भी राहुल को हो रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे नेता के न होने का फायदा राहुल को ही मिलने जा रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे लोकसभा चुनाव में कोई मजबूत विपक्षी नेता न होने का लाभ नरेंद्र मोदी को मिला था. ■■

बांग्लादेश के साथ मजबूत होंगे रिश्ते

कुलदीप तलवार
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते बांग्लादेश जा रहे हैं. प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी बांग्लादेश की यह पहली यात्रा है. यह यात्रा भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ मेल-

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा से दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और दोस्ताना रिश्तों को और मजबूती मिलेगी.

जोल बढ़ाने की मोदी सरकार की नीति का एक हिस्सा है. 2009 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में नजदीकी आई है. माना जा रहा है कि मोदी की यात्रा से दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूती मिलेगी. भूमि सीमा विवाद का मुद्दा जो पिछले 40 सालों से लटका था, मोदी ने इसे संसद में निर्विरोध पारित कराकर अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति का सबूत दिया है.

दरअसल मोदी का बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा विवाद खत्म करना और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने अपने देश पर पड़ने वाले आर्थिक असर की परवाह किए बिना इस समझौते में असम के कुछ हिस्सों को भी शामिल कराया. पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये समझौता भारत के हितों के खिलाफ है क्योंकि भारत को बहुत कम जमीन जो बांग्लादेश के अधिकार में थी, मिलेगी. लेकिन इसके बदले में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से बांग्लादेश को मिलेगा. बहरहाल, इस समझौते का भारत को फायदा भी होगा. भारत के लिए अब सीमा पर बाड़ लगाना आसान हो जाएगा. इसके लगने से सीमा पर से होने वाली घुसपैठ भी बंद हो जाएगी. इस समझौते से पता चलता है कि अगर इरादे नेक और बुलंद हों तो सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा सकता है. इससे यह भी पता चलता है कि मोदी सरकार ने पहला कदम बढ़ाकर बता दिया है कि वह ढाका को लेकर गंभीर हैं.

उम्मीद की जा रही है कि मोदी के बांग्लादेश के दौरे में जहां उक्त समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होंगे वहीं यह समझौता प्रमुख द्विपक्षीय विवादित तीस्ता जल साझा समझौते को गति देने में सहायक होगा, जिससे भारत को कई अन्य विवादास्पद मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए समुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा. जिनमें बांग्लादेश से होकर उत्तर-पूर्व को ज्यादा पहुंच तथा आतंकवाद विरोध में अधिक सहयोग शामिल है. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और दोस्ताना रिश्तों को और मजबूती मिलेगी. ■■

नजर के पार

विकास से ही खत्म होगा नक्सलवाद

विष्णुगुप्त
वरिष्ठ स्तंभकार

विकास, न्याय व सम्मान, ये तीन ऐसी अनिवार्य मानवीय जरूरतें हैं जिन्हें पाने के लिए कोई हाड़तोड़ मेहनत करता है, कोई आंदोलन करता है, कोई संघर्ष करता है, कोई विद्रोह का बिगुल बजाता है, कोई हिंसक होकर हथियार उठाता है तो एक प्रजाति ऐसी भी है जो विकास, न्याय और सम्मान को लूटने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाती है. दुनिया के हर कोने में परिश्रमी वर्ग और लुटेरे वर्ग के बीच ऐसी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है. ऐसी प्रतिद्वंद्विता का दुष्परिणाम यह होता है कि हम हिंसक मानसिकता की चपेट में आ जाते हैं और हिंसा से न केवल मनुष्य की कीमती जानें जाती हैं बल्कि विकास व उन्नति का रास्ता भी कठिन व दुरूह हो जाता है. हमारे देश में जो नक्सलवाद है उसकी जड़ में विकास, न्याय व सम्मान पाने का हिंसक संघर्ष ही है. यह कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए कि विकास, न्याय व सम्मान के लिए हाड़तोड़ मेहनत करने वालों और विकास, न्याय व सम्मान के लिए अहिंसक लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों व उनके समूहों का विश्वास नहीं डिगने दिया जाता तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद को इतनी बड़ी समर्थक जमीन नहीं मिल सकती थी और न ही नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर व हिंसक चुनौती देता. शासक वर्ग सिर्फ एयर कंडीशन में बैठकर हवा-हवाई नीति घोषित करते हैं कि विकास करो, प्रतिहिंसा में सेना व पुलिस को बर्बर बनाओ और नक्सलवाद की समस्या का हल करो. यह नीति कभी भी चाकचौबंद नहीं मानी जाएगी. सिर्फ विकास ही नहीं,

विकास में सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, त्वरित व सस्ती न्याय उपलब्ध कराना होगा, सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक तौर सम्मान की राजनीतिक-सामाजिक नीति कायम करनी होगी, तभी नक्सलवाद की धधकती आग बुझ सकती है.

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर का दौरा कर यह कहा कि विकास के रास्ते में हम नक्सलवाद का सफाया करेंगे और देश के जिन-जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद का दबदबा है, उन-उन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, केंद्रीय सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में और तेजी लाएगी. नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं, सुविधाओं का अभाव है, बिजली, पानी और सड़क का हाल निम्न स्तर तक का भी नहीं होता है. यही कारण है कि नक्सली ऐसे क्षेत्रों को अपनी पनाहगार के तौर पर चुनते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से समर्थक जमीन भी तैयार कर लेते हैं. ऐसे पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्र का विकास करना एक अच्छी बात है. पर विकास का नजरिया कैसा है, विकास का रास्ता कैसा है, विकास में स्थानीय लोगों की सहभागिता है या नहीं, विकास कहीं जल, जंगल, जमीन को लूटने वाला तो नहीं है, विकास कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचा कर दलालों, नौकरशाहों, कार्पोरेट घरानों और राजनीतिज्ञों की तिजोरी भरने वाला तो नहीं है, इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. ■■

तोल बोल

जब हम मिलकर चले हैं लड़ने के लिए तो एक-दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा. विश्वास का संकट दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा.

■ लालू प्रसाद यादव, राजद प्रमुख

नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान चकाचौंध भरा था. क्या बिना सूटकेस लिए ऐसा अभियान चलाना संभव था ?

■ तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम

gnWnHi gnXHi :
nd. Odhnabnb XSn
M`a_Z, E{SQn{a`b ~nS :
{dO~ XSn
E{SQa-BZ-Mr\i :
anOb XSn
gnXH :
{dHbg {_I ★
★ nr. Aa. ~r. HbZZ Hi
AZgn gnU gnXHi` Xq{`Ed
Hi {bE {Oa_Xa.

© लोकमत समाचार _ àHi{eV g^r gr_Jr Hi gdr{YHia bHi_V r{S`n àr`d{ {b. Hi nrg ga{jV h.
bHi_V r{S`n àr`d{ {b. Hi {bE _ÐHi Ed àHieHi बालाजी मुले Ûiat bHi_V r{S`n àr. {b., ibr{Q Hi. 192, 207, 208 E., AiB. Sr. gr. B\S{fO` b E{a`n, ~Q{~ar, Z:Jna _{ÐV Ed bHi_V ^dZ n. Odhnabnb ZHi _nJ, Z:Jna _ àHi{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaUd{Z : 0712-2423527 (7 bBIg) \ISg : 6618555
Email : gnXHi` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkInZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 3 जून

आज ही के दिन 1987 में लियों में नाजी पार्टी की खुफिया पुलिस के पूर्व प्रमुख क्लाउस बार्बी को मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 73 साल के क्लाउस बार्बी पर दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 842 लोगों को यातना शिविर में भेजने का आरोप लगाया गया था. इन भेजे जाने वाले लोगों में अधिकतर यहूदी थे. नीदरलैंड में जर्मनी की सेना में कमान संभालने के बाद क्लाउस बार्बी 1942 में नाजी पार्टी की खुफिया पुलिस का प्रमुख था. इस बात के भी प्रमाण मिले कि क्लाउस बार्बी यातना शिविर में बंद लोगों को खुद ही अमानवीय यातना देता था. 1991 में लियों की जेल में ही क्लाउस बार्बी की मौत हो गई. ■■

- 1915-ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रवींद्रनाथ टैगोर को 'नाइटहुड' से अलंकृत किया.
- 1943-संयुक्त राष्ट्र राहत एवं पुनर्वास प्रशासन की स्थापना.
- 1947-भारतीय राजनेताओं ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित भारत विभाजन को स्वीकार किया.
- 1968-कनाडा ने निकेल के सिक्कों को चांदी में बदलने की घोषणा की.
- 1985-भारत सरकार ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू किया.
- 1989-चीनी सेना ने बीजिंग में आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों पर गोलियां बरसाईं.

पाठकों के पत्र

बेबाक टिप्पणी

फुसफुसाहट के माध्यम से दुष्प्रचार फैलाने की संघ की शैली पर अपनी बेबाक टिप्पणी से आपने उसका छिपा चेहरा उजागर कर दिया. इसके लिए बधाई! बाबासाहब के नाम का विरोधाभासी उपयोग भाजपा की भी विशेषता बन गई है.

■ पार्थ गर्ग, नागपुर

पश्चिम का बढ़ता प्रभाव

आजकल की फिल्मों में सेंसर की कैंची के बावजूद अश्लीलता की भरमार होती है. देश के युवाओं में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और शहरों में बलात्कार जैसे अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं. प्रशासन को भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए शहरों के सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता की हद में आने वाली फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए, ताकि युवाओं के कदमों को गलत दिशा में जाने से रोका जा सके.

■ कय्यूम खान, नागपुर

नास्तिक गोताखोर

एक युवक ओलंपिक में गोताखोरी के प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था. उसके जीवन में धर्म का महत्व केवल इतना ही था कि वह अपने बड़बोले ईसाई मित्र की बातों को कभी-कभार बिना कोई प्रतिवाद किए सुन लेता था. उसका मित्र नियमित रूप से चर्च जाता था और वापस लौटकर युवक को बाइबिल के उपदेश सुनाया करता. युवक अपने मित्र की बातों को सुन तो लेता लेकिन उन पर कुछ ध्यान नहीं देता था.

विविध

एक रात युवक गोताखोरी के अभ्यास के लिए इन-डोर स्वीमिंग पूल गया. वहां रोशनी नहीं थी. इन-डोर स्वीमिंग पूल की छत कुछ खुली हुई थी और चंद्रमा का कुछ प्रकाश भीतर आ रहा था. उतनी रोशनी में युवक अपना अभ्यास कर सकता था.

युवक सबसे ऊंचे डाइविंग प्लेटफॉर्म पर गया. डाइविंग बोर्ड के किनारे खड़े होकर उसने गोता लगाने की तैयारी में अपनी बांहें फैलाईं. बाजू की दीवार पर उसे अपनी परछाईं दिखाई दी. परछाईं में उसका शरीर सलीब पर चढ़े ईसा की तरह दिख रहा था.

यह देखकर युवक के मन में श्रद्धा उमड़ आई. उसने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की. प्रार्थना करने के बाद वह गोता लगाने के लिए तैयार होने लगा.

तभी वहां पूल के एक कर्मचारी ने आकर बत्तियां जला दीं.

युवक ने देखा, पूल में एक बूंद भी पानी नहीं था क्योंकि उसके रखरखाव का काम चल रहा था. ■■